

ont>

### **Title: Need to have a transparent policy on disinvestment- Laid.**

**श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजबाद):** अध्यक्ष महोदय, विनिवेश के संबंध में स्पट और सुविचारित नीति के अभाव में सरकार आरोपों से लगातार घिरती जा रही है। मामला सी.एम.सी का हो या सैंटूर होटल का, देश का आम आदमी मानने लगा है कि सरकार में बैठे लोग अपने लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने में लगे हैं। हिन्दुस्तार पेट्रोलियम अथवा भारत पेट्रोलियम इकाइयों को बेचने के प्रस्ताव ने लोगों में धारणा बलवती बना दी है। सरकार उपरोक्त आरोपों के जवाब में कहती है कि देश के पैसे को न तो बरबाद होने दिया जायेगा और न सरकारी लोगों को व्यापार के बहाने लूट का अवसर दिया जायेगा। बी. पी सी एल व एच.पी. सी एल को निजी क्षेत्र को सौंपना और ओ.एन.जी.सी., गैल, पॉवर ग्रिड कारपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड आदि सरकारी कम्पनियों को न देश में बल्कि विदेशों में पूंजी निवेश की खुली छूट सरकार द्वारा देना स्वयं में विरोधाभास पैदा करता है।

अतः मेरा आग्रह है कि सरकार विनिवेश नीति का स्पट निर्धारण करे और उस पर अमल करे, जिससे आम आदमी का विश्वास सरकार जीतेगी ही देश की भी सही से वा कर पायेगी।